दिल्ली के प्रशासनिक ढांचे के संबंध में सरकारिया समिति का प्रतिवेदन

*47. सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा :
श्री राम जेठमलानी :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार को दिल्ली प्रशासन के ढांचे के संबंध में सरकारिया समिति का प्रतिवेदन प्राप्त हो चुका है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार इस संबंध में क्या कार्य योजना तैयार कर रही है ;

(ग) क्या यह सच है कि सरकार दिल्ली को राज्य का दर्जा देने के प्रस्ताव पर सहमत हो गई है ; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रस्ताव को लागू करने के मार्ग में यदि किन्हीं रुकावटों के आड़े आने की सम्भावना है तो उनका ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्री (श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद) : (क) से (घ) समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को 14 दिसम्बर, 1989 को ही प्रस्तुत की है और इस समय इसकी जांच की जा रही है ।

SARDAR JAGJIT SINGH AURORA : Mr. Chairman, Sir, may I ask one thing ? It is my question.

MR. CHAIRMAN : Yes. I am looking towards you.

SARDAR JAGJIT SINGH AURORA : may I please ask the hon. Minister whether he can please give us an idea when they are likely to finish the examination because people want to know whether Delhi is going to become a State or not, because then the elections are to be held? So, have hey given themselves any time-frame with regard to coming out with their views on this report? Thank you.

SHRI MUFTI MOHAMMAD SAYEED : Sir, the report has been submitted to the Government on the 14th December, 1989. And we think that we should place the report of the Committee on the Table during the current session. Then we will try to consult all the parties about the recommendations, when they are placed on the Table of the House. Then there should be interaction with different parties about the new set-up. Whatever recommendation is made by the Sarkaria Committee there are three or four options that hey have given us. We shall have to consult different parties.

SARDAR JAGJIT SINGH AURORA : No more questions.

SHRI RAM JETHMALANI : Sir, I hope the hon. Minister will realise that before publishing this report there is another report which has got to be published, i.e. 6,000 odd pages of the Thakkar Commission Report. That is more urgent than this report.

SHRI VISHWA BANDHU GUPTA : Sir, as a Delhi-walla I feel tha just because we happen to be living where the seat of the Central Government exists, the rights of the Delhi citizen have always been curtailed. And we have difficulties because we have not only to deal with the Administration at Delhi but we are to be totally controlled by the Central Government. Now, this anomaly has been examined by the Sarkaria Committee the multiplicity of authorities in Delhi to which the citizens have to turn, to get any of their problems solved. We have the Municipal Corporation of D lhi. We have the Metropolitan Council. As far

*सभा में यह प्रश्न सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा द्वारा पूछा गया ।

as the question of Statehood for Delhi is concerned, it is being examined and the hon. Minister has very kindly said that he will consult the various parties and I hope, they will also consult the largest party here, in Parliament. While this process of trying to figure out the status for Delhi will take some time, I would like to know from the hon. Minister whether the Delhi Municipal Corporation and the Metropolitan Council are going to be superseded soon, or, are they going to get another extension? What is the view of the Government on this issue.

SHRI MUFTI MOHAMMAD SAYEED : Sir, as far as the Sararia Committee report is concened, Part I of the report contains the views and the recommendations of the Committee on the restructuring of the Government set-up in Delhi and Part II contains the recommendations of the Committee relating to the reorganisation of the municipal and other authorities functioning in Delhi. Certainly, it will take some time to consider the report.

SHRI VISHWA BANDHU GUPTA : I asked whether these two bodies are going to be superseded the Delhi Municipal Corporation and the Metropolitian Council. Is the hon. Minister thinking of superseding them, or, giving them extension?

SHRI MUFTI MOHAMMAD SAYEED : The Delhi Municipal Corporation has been given three extensions and the Metropolitan Council, two extensions. It is under the active consideration of the Government.

श्री अश्विनी कुमार : माननीय सभापति महोदय, दिल्ली के लिए जो सरकारिया कमीशन बना था उसका मूल उद्देश्य था कि यहां जो विविध संस्थायें हैं, उन सब को मिलाकर एक राजनैतिक ढांचा बनाया जा सके जिससे दिल्ली के नागरिक एक स्थान पर अपना काम करा सकें जैसा कि मेरे पूर्व वक्ता ने कहा। जहां तक मेरी जानकारी है जितने भी राजनैतिक दल हैं, कांग्रेस (आई) भी इसमें शामिल है, जनता दल है, बी०जे०पी० है, इन सब लोगों ने दिल्ली को एक राजनैतिक ढांचा देकर स्टेट हुड देने का प्रस्ताव अपने अपने घोषणा पत्र में किया है इसे बार बार कहा है। इसलिये कंसलटेशन की जो बात है उसके अंदर कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। मैं मंत्री महोदय से केवल यह जानना चाहता हूं कि जो आसन्न चुनाव है, जो अगले दो महीनों में होने वाला है क्या वे उसके पहले निर्णय कर पायेंगे या उसके बाद करने की उनकी इच्छा है?

श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद : मैंने पहले ही कहा है कि जो सरकारिया कमीशन की सिफारिशात है, जो भी उन्होंने सुझाव दिये है एक तो यह है कि पहले उन्होंने जो रिपोर्ट पेश की है तो हमारे लिये यह मुनासिब नहीं है कि उस रिपोर्ट की सिफारिशात को हम पहले ही कहे कि वे क्या है। उसमें एक आप्शन है कि दिल्ली बींइग दि कैपिटल आफ दि कन्ट्री, इसमें कुछ मुश्किलात हैं इस बारे में हम जितनी भी पार्टीज के रहनुमा है, नेता है उनसे बातचीत करके ही फैसला कर सकेंगे। बाकी पिछले तीस साल से जिस सेट-अप के बारे में गौर हो रहा है और यह तीस साल मे नहीं हो सका है, उस पर एक-दो दिन में फैसला नहीं हो सकता है वह एडहाक बेसिस पर नहीं हो सकता है।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि दिल्ली म्युनिस्पल कारपोरेशन और दिल्ली मैट्रोपोलिटन कौंसिल इन दोनों का चुनाव केवल पांच वर्ष के लिए हुआ था और केवल पांच वर्ष के लिए जनता ने इन दोनों को चुना था। उसके बाद पहली सरकार ने एक साल इसका कार्यकाल बढ़ाया और उसी सरकार ने फिर इनका और कार्यकाल बढ़ाया। मेरा प्रश्न केवल यह है कि सरकारिया समिति का जो

प्रतिवेदन है, जिसके ऊपर आप विचार कर ही रहे हैं तो कम से कम आप स्पष्ट आश्वासन दीजिए कि म्युनिस्पल कारपोरेशन और मैट्रोपोलिटिन कौंसिल, इनका कार्यकाल अब नहीं बढ़ायेंगे ?

श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद : मैंने पहले ही कह दिया है कि म्युनिस्पल कारपोरेशन का जहां तक ताल्लुक है उसका पहले ही तीन साल का टर्म एक्सटेंड कर दिया गया है। पांच साल का आठ साल हुआ है। इसी तरह मैट्रोपोलिटन कौंसिल पांच साल के लिए थी उसका सात साल हो गया तो यह मुनासिब नहीं होगा। इसका जो रिप्रजन्टेटिव करेक्टर था वह खत्म हुआ है। इसलिए सरकार के गौर में यह बात है कि इसके बारे में क्या किया जाय।

Statutory Development Boards for Vidarbha Marathwada and Konkan

*48. DR. BAPU KALDATE: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether the proposal for setting up of Statutory Development Boards for Vidarbha, Marathwada and Konkan region is likely to be cleared shortly as assured by the Prime Minister during his recent visit to Nagpur; and

(b) if so, the action taken by Government in this regard and at what stage the proposal stands?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI MUFTI MOHAMMAD SAYEED): (a) and (b) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) A draft scheme for giving effect to the provisions of article 371(2) of the Constitution was received from the Government of Maharashtra in February, 1989. It comprised of a draft order to be made by the President under the said provision and a draft order to be issued by the Governor in pursuance thereof, providing *Inter-alia* for establishment of Development Boards for Vidarbha, Marathwada and the rest of Maharashtra. After examination, the Government of Maharashtra have been requested to consider recasting the Governor's order keeping in view the requirements of the State and legal opinion.

(b) The Government of Maharashtra made a proposal in April, 1989 for amending article 371(2)(a) so as to include a specific provision for establishment of a separate development board for Konkan also. This proposal was examined and the State Government were requested to furnish information on certain points to facilitate examination of the matter in proper perspective. The requisite information has been received. In deference to the wishes of the State Government, it was however, decided to defer consideration of this matter and expedite action in regard to the implementation of the scheme referred to above.

डा० बापू कालदाते : सभापति महोदय, इस सवाल को हम पांच साल से बार बार उठाते रहे हैं। पिछली सरकार का कार्यकाल समाप्त हो गया है। हम यह जरूर मानते हैं कि हमारी सरकार इस बारे में जितनी देर उन्होंने लगाई है उतनी देर नहीं लगाएगी। इतना ही नहीं बल्कि जल्दी से जल्दी इस काम को पूरा करेगी इसमें मुझे शक नहीं है। महोदय, स्वर्गीय वसन्त दादा पाटिल से ले कर आज तक यह मामला चलता आया है। महाराष्ट्र विधान-मण्डल ने एक राय से यह प्रस्ताव पारित किया था कि संविधान के अनुच्छेद 371 (2) के तहत विकास बोर्ड की स्थापना की जाए। फिर माननीय शंकरराव चव्हाण जी गृह मंत्रालय का कार्यभार सम्भालते थे तब भी यह नहीं हो पाया। फिर वे वहां के मुख्य मंत्री बने। उनकी राय कुछ अलग हो सकती है लेकिन बहुत